



भारत में एआई अपनाने की दर
सिर्फ 14.2%
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई
अपनाने की दर 14.2 प्रतिशत है,
जिससे भारत 65वें स्थान पर है।

संपादकीय

जहरीली हवा में घुटती सांसें

दशकों से मीडिया व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग तथा संगठन, जिस प्रदूषण संकट के प्रति चेताते रहे हैं, उसके घातक परिणाम अब साफ सामने नजर आने लगे हैं। विडंबना यह है कि देश की राजधानी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही नहीं, अब देश के तमाम बड़े-छोटे शहरों से भी जानलेवा प्रदूषण की खबरें आ रही हैं। इस घातक व मारक संकट की पुष्टि बहुचर्चित मेडिकल जर्नल लैंसेट की हालिया रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट दावा करती है कि देश की हवा में २०१० की तुलना में साल २०२२ तक प्रदूषणवाहक पीएम २.५ कणों की मात्रा में ३८ फीसदी तक का बढ़ावा हुआ है। जिसका घातक प्रभाव यह है कि करीब सत्रह लाख लोग असमय काल-कवलित हो चले हैं। इससे होने वाला आर्थिक नुकसान अलग है। यह कहना कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। बहुत संभव है कि सरकारें इन आंकड़ों पर सहमति न जताएँ, लेकिन दीपावली के बाद दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के विभिन्न शहरों में प्रदूषण जिस घातक स्तर तक पहुँचा है, वह हालात के गंभीर होने की ओर इशारा तो करता ही है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दिल्ली को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का खिताब भी दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अस्पतालों में प्रदूषणजनित रोगों का उपचार करने वाले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। जीवन के संघर्ष में रोड़ी-रोटी की कवायद में जुटे लोगों को यह अहसास भी नहीं होता है कि वे दिन में कितनी जहरीली हवा निगल रहे हैं। हमारे शहर केंद्रित विकास की विस्मयितां भी शहरों में प्रदूषण का कारगर बढ़ा रही हैं। शहरों में उगते कंक्रीट के जंगल न केवल हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहे हैं बल्कि वाहनों के सैलाब को भी बढ़ावा दे रहे हैं। विडंबना यह है कि इसके बावजूद राजनीतिक दलों व सरकारों ने वह इच्छाशक्ति नजर नहीं आती, जो इस संकट के कारगर समाधान की राह दिखाती हो।

निश्चित तौर पर प्रदूषण संकट की यह जानलेवा स्थिति हमें शर्मसार करने वाली है। यह हमारी सामूहिक विफलता की तसवीर भी उकेरती है। सदियों का मौसम आते ही दिल्ली व निकटवर्ती शहरों में जो प्रदूषण का बड़ा संकट दिखायी देता है, आखिर उसे साल भर सतर्कता के साथ क्यों नहीं देखा जाता। देश में आर्थिक असमानता व गरीबी के चलते लाखों लोग व बच्चे उन अस्वस्थकारी परिस्थितियों में काम करने को बाध्य हैं, जो कालांतर जानलेवा रोगों का सबब बनती हैं। देश में करोड़ों बाल श्रमिक पटाखा, कालीन और अन्य सांस के रोगों का संकट बढ़ाने वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं। व्यवस्था का भ्रष्टाचार नियामक एजेंसियों को हिलने तक नहीं देता। दरअसल, यह प्रदूषण मौसमी बदलाव, पटाखों या पराली जलाने से ही नहीं पैदा होता। दरअसल, इसके मूल में शासन-प्रशासन की वह विफलता भी शामिल है, जो वातावरण को जहरीला बनाने वाले उद्योगों तथा निर्माण में उड़ने वाली धूल की सतर्क निगरानी नहीं करती। दरअसल, हमारे जीवन की कृत्रिमता व सुविधाभोगी जीवनशैली ने उन घातक गैसों को बढ़ावा दिया जो ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण की कारक बनती हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि देश की जनता इस आसन्न संकट के प्रति लगातार उदासीन बनी रहती है। वह चुनावों के दौरान न तो राजनेताओं पर इस संकट के समाधान के लिये दबाव बनाती है और न ही निजी जीवन में ऐसी कोई पहल करती है। इस तरह कहीं न कहीं इस प्रदूषण वृद्धि में हमारी भागीदारी बनी हुई है। अब भले ही कार्बन उत्सर्जित करने वाले ईंधन के उपयोग में कमी आई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हम निजी जीवन में जितनी स्क्व्ड ऊर्जा को बचावा देंगे, उतना ही प्रदूषण धीरे-धीरे कम होता जाएगा। जनता को शासन-प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि वह समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के लिये प्रयास करे। व्यक्ति के तौर पर हमें पटाखे व पराली जलाने वालों की निगरानी करनी होगी, ताकि प्रदूषण का स्तर कम करने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

अभियान

कार्तिक में तुलसी चालीसा का विशेष महत्व : श्रीहरि की कृपा से बदल जाएगी किस्मत

हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और शुभ महीना कहा गया है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश-भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। यह वही काल होता है जब वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा फैल जाती है — दीपों की पंक्तियों से जगमगाते घर, संध्याकालीन आरतियाँ, तुलसी चौरा पर जलते दीप और मंदिरों में गुंजते शंखध्वनि, ये सब मिलकर पूरे वातावरण को एक दिव्य चेतना से भर देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का आठवां महीना है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में श्रीहरि विष्णु के आराधना करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप से तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं श्रीहरि की अर्धांगिनी मानी जाती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर

अनेक रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की, तब उन्होंने देवी लक्ष्मी के रूप में तुलसी को अपना प्रिय बनाया। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए हर मंदिर में विष्णु प्रतिमा के आगे तुलसी पत्र का अर्पण आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी का एक पत्र भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए, तो वह सहस्र स्वर्णदान के समान फल देता है। कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। तुलसी चालीसा न केवल भक्ति का एक स्तोत्र है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, समृद्धि और शुभता का संचार करती है। जब भक्त तुलसी के पौधे की सम्मुख दीपक जलाकर श्रद्धा से तुलसी चालीसा का पाठ करता है, तब उसके चारों ओर एक अद्भुत साकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। कहा जाता है कि इस समय श्रीहरि विष्णु और तुलसी माता स्वयं अपने भक्त के समीप उपस्थित होकर उसके पापों का नाश करते हैं। तुलसी पूजा का समय प्रातःकाल या संध्याकाल सर्वोत्तम माना गया

“

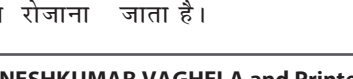
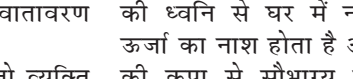
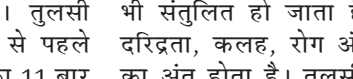
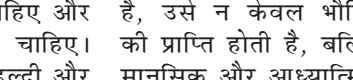
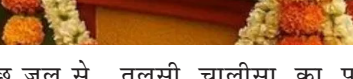
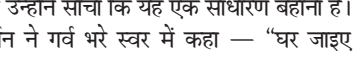
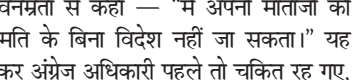
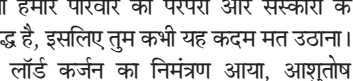
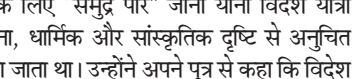
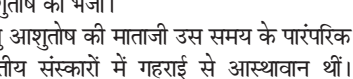
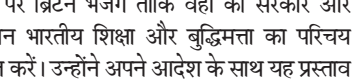
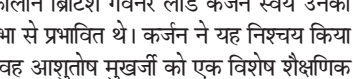
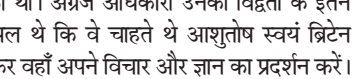
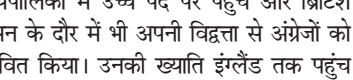
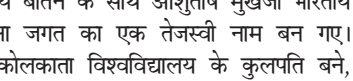
एक नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ की उम्र चौथाई सदी पूरी कर चुकी है। इस राज्य के जन्म के लिए धरनारत रहे उस व्यक्ति का नाम लोग भूल चुके हैं। राजनेताओं की लंबी फेहरिस्त राजनीतिक क्षितिज पर अपनी अच्छी-बुरी उपलब्धियों के साथ चमक रही है। लेकिन ढाऊ आनंद अग्रवाल का संघर्ष कहीं खो गया है।

प्रेरणा

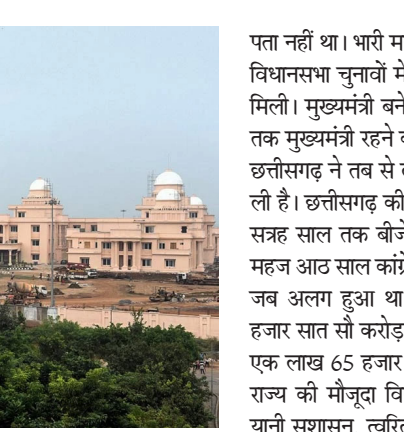
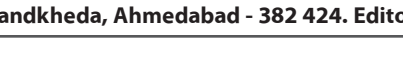
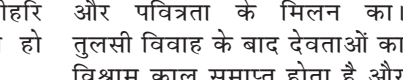
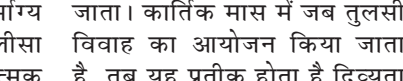
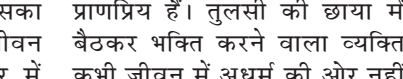
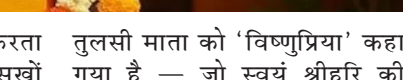
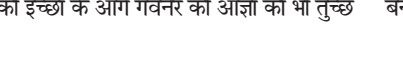
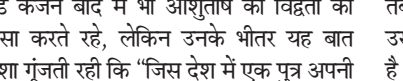
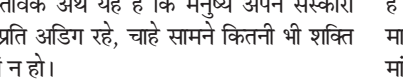
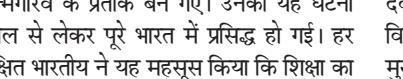
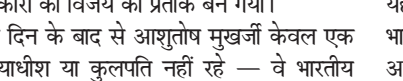
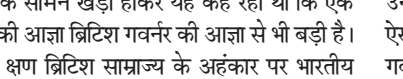
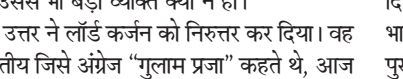
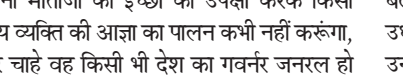
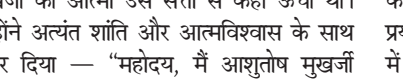
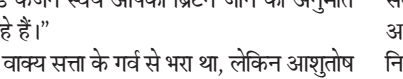
गवर्नर से बड़ी मां की आज्ञा : भारतीय संस्कारों की अमर गाथा

भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से यह सिद्ध कर देते हैं कि शिक्षा केवल डिग्रियों से नहीं, बल्कि संस्कारों से पूर्ण होती है। ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर आशुतोष मुखर्जी की, जिन्हें भारतीय शिक्षा-जगत का “बंगाल का लायन” कहा जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान, मातृभक्ति और भारतीयता का गौरव न केवल उस युग में बल्कि आज भी प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। यह घटना उस समय की है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेज शासन की कठोर नीतियों और सांस्कृतिक अहंकार के बीच भारतीयों के आत्मसम्मान को बार-बार चुनौती दी जा रही थी। ऐसे दौर में जब बहुत से लोग सत्ता के भय से झुक जाते थे, तब कुछ ऐसे तेजस्वी भारतीय थे जो आत्मगौरव के साथ खड़े रहना जानते थे। आशुतोष मुखर्जी उन्हीं में से एक थे — ज्ञान, चरित्र और आत्मबल के प्रतीक। आशुतोष मुखर्जी का बचपन अत्यंत साधारण परिस्थितियों में बीता था। उनके पिता का निधन बहुत पहले हो गया था, और उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण किया। माताजी ने अपने पुत्र को यह सिखाया कि विद्या का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता और संस्कृति का पालन करना भी है। इसी मातृसंस्कार ने उन्हें इतना दृढ़ बना दिया कि जीवन में किसी भी पद या सत्ता के सामने वे कभी झुके नहीं।

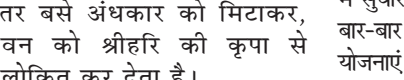
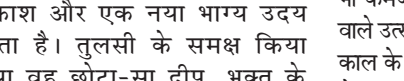
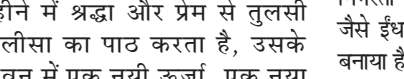
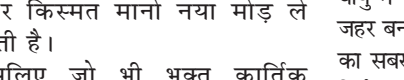
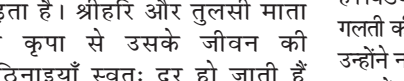
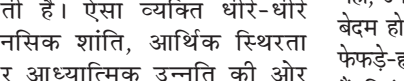
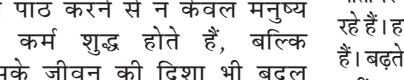
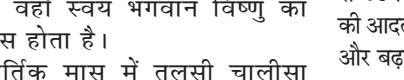
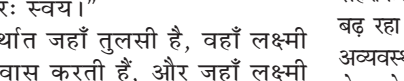
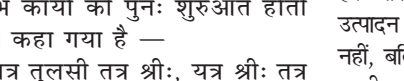
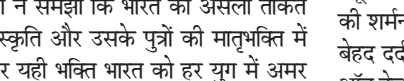
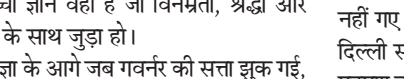
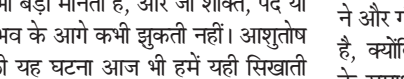
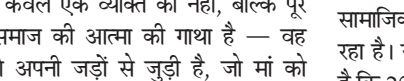
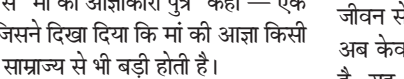
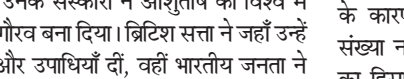
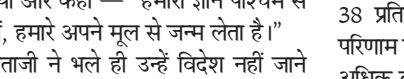
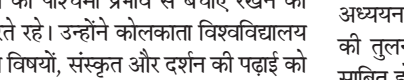
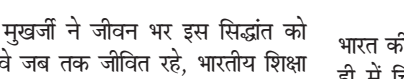
इक्कीसवीं सदी की आहट सुनाई देने लगी थी..उन दिनों इन पंक्तियों का लेखक मध्य प्रदेश-राजस्थान के एक बड़े अखबार का दिल्ली में संवाददाता था.. उस दिन खबरों का सूखा था..उसे दूर करने की नीयत से इन पंक्तियों का लेखक धरनों के लिए विख्यात जंतर-मंतर पर जा पहुँचा..वहां जाकर देखा, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग को लेकर साधारण-सा व्यक्ति धरने पर बैठा था..साथ में गिनती के विश्वासपात्र ही बैठे थे..प्ता चला कि धरनारत उस व्यक्ति के पास खाने तक के पैसे नहीं थे..उनसे पता चली कि रात को रोजाना अपनी क्षुधा शांत करने के लिए पास ही स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब या फिर रकाब जाते और वहां के लंगर से अपनी भूख शांत करते थे.. उनके साथियों का भी यही हाल था..व्नोपज और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य का धरना और उसे सहारा लंगर का..मर्म को छूने वाली वह खबर थी..खबर लिखी थी, ‘लंगर के सहारे चलता अलग राज्य का धरना’.. खबर छपते ही रायपुर और उसके आस-पास हलचल मच गई। तब आज की तरह फोन नहीं थे..लेकिन लोग उस धरना देने वाले व्यक्ति का पता पछुने और उन तक अपनी श्रद्धा भरा पहुँचाने की जैसे होड़ लग गई.. एक नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ की उम्र चौथाई सदी पूरी कर चुकी है। इस राज्य के जन्म के लिए धरनारत रहे उस व्यक्ति का नाम लोग भूल चुके हैं। राजनेताओं की लंबी फेहरिस्त राजनीतिक क्षितिज पर अपनी अच्छी-बुरी उपलब्धियों के साथ चमक रही है। लेकिन ढाऊ आनंद अग्रवाल का संघर्ष कहीं खो गया है। पता नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों, विशेषकर प्रबुद्ध लोगों को, उनका नाम याद है भी या नहीं। उन दिनों छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख दैनिक के दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे विनोद वर्मा बताते हैं कि ढाऊ के एक वक्त का भोजन अखबारों के प्रमुख दफ्तर आईएनएस बिल्डिंग की कैटीन में होता था..जिसका खर्च विनोद वर्मा उठाते थे। यहां बात दें कि विनोद वर्मा बाद के दिनों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे।



आनंद अग्रवाल को ही क्यों, बहुत लोगों को पवन दीवान की भी याद नहीं होगी। पवन दीवान बुनियादी रूप से समाजवादी नेता थे। यह बात और है कि उन्होंने बाद में राजनीतिक दलों में खूब आवाजही की। कभी बीजेपी के कमलधारक बने तो कभी कांग्रेस के हाथ का साथ लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। दिल्ली के जंतर-मंतर पर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। छत्तीसगढ़ अब अलग राज्य के रूप में फल-फूल रहा है। लेकिन उसे मध्य प्रदेश से अलग राज्य बनाने की पहली बार ठोस मांग करने वाले खूबचंद बघेल के नाम को कितने लोग याद करते हैं, पता नहीं। पिछली सदी के साठ के दशक के आखिरी वर्षों में उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ बनाया था और अलग राज्य की उन्होंने मांग को पहली बार ताकतवर सुर दिया था। जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग रखी, उनकी मांग का आधार था छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, वनोपज और खूबसूरत नजारें। सबका मानना था कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वनोपज और खनिजों की वजह से छत्तीसगढ़ कहीं ज्यादा समृद्ध है, लेकिन उसका फायदा उसके निवासियों को नहीं मिल रहा है। उस पर कब्जा राज्य के दूसरे इलाके के लोगों और राजनीतिक वर्चस्व वाली ताकतों को मिल रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने

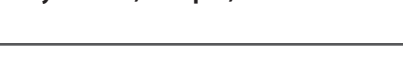
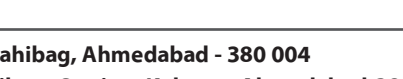
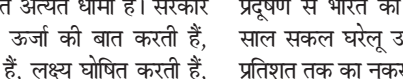
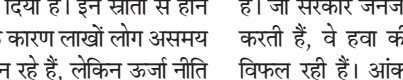
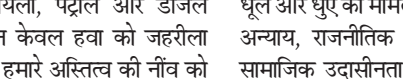
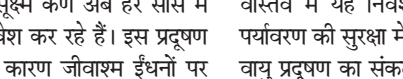
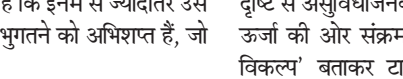
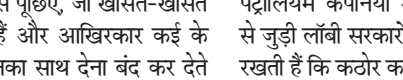
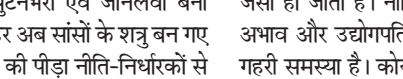
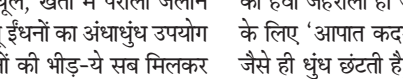
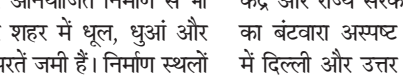
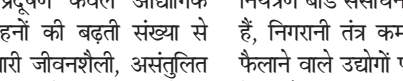
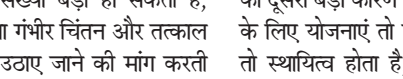
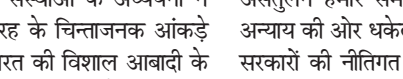
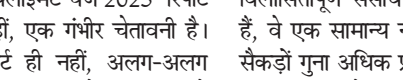
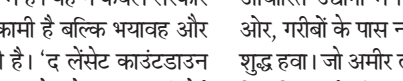
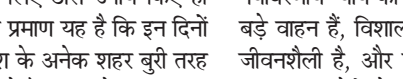
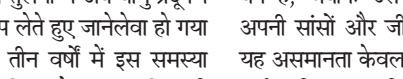
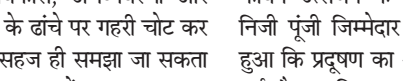
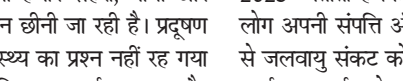
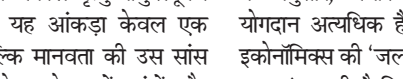
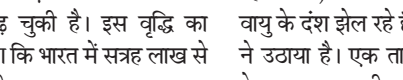
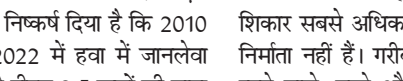
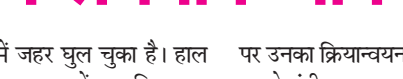


की मांग १९२४ में रायपुर में हुई थी। लेकिन तब देश गुलाम था, अंग्रेजी दासता से मुक्ति तब पहला उद्देश्य था। लिहाजा यह मांग सिर से परवान नहीं चढ़ पाई। दिलचस्प यह है कि जिन्होंने अलग राज्य की मांग रखी, राजनीतिक रूप से उनका आज कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे बिड़बना कहें कि कुछ और, यह स्थिति छत्तीसगढ़ के साथ बसे उत्तराखंड राज्य की भी है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सबसे जोरदार आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल ने चलाया, उसकी कीमत भी चुकाई। मुजफ्फरनगर कांड उस कीमत की चरम परिणति कही जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड में आज उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और वाक्या याद आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा चुनाव २००३ में हो रहा था। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने एक साल पहले ही शुरू कर दी थी। उन दिनों केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। उस सरकार में रमन सिंह इस्यत राज्य मंत्री थे। बीजेपी ने तय किया कि उन्हें चुनावी तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ बिहार से भी छोटा है। बिहार की जनसंख्या करीब तेरह करोड़ से कुछ ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ रकबा के लिहाज से बिहार से डेढ़ गुना बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के



पता नहीं था। भारी मन से वे छत्तीसगढ़ गए, लेकिन विधानसभा चुनावों में उनकी अगुआई में भारी जीत मिली। मुख्यमंत्री बने और लागातार तीन कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने का उन्हें स्वर्णिम मौका मिला।

छत्तीसगढ़ ने तब से लेकर अब तक लंबी यात्रा कर ली है। छत्तीसगढ़ की पच्चीस साल की इस यात्रा में सत्रह साल तक बीजेपी का शासन रहा है, जबकि महज आठ साल कांग्रेस की सरकार रही। छत्तीसगढ़ में जब अलग हुआ था तो उसका बजट महज पांच हजार सात सौ करोड़ का था। आज राज्य का बजट एक लाख ६५ हजार सौ करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार इसे गति यानी सुशासन, त्वरित अवसरचरना, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास की थीम पर आधारित बजट बता रही है। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो वहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, वहां एकमात्र मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर था। यह कॉलेज १९६३ में स्थापित किया गया था और इसे रायपुर मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज १४ मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें ११ सरकारी, एक एम्स और ३ निजी कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में ४ नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की घोषणा की जा चुकी है। ये कॉलेज बन गए तो उनकी संख्या १८ हो जाएगी। कह सकते हैं कि राज्य ने मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा ली है। छत्तीसगढ़ को लेकर एक छवि यह है कि वह छोटा राज्य है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। उसे छोटा मानने की वजह उसकी अपेक्षाकृत कम जनसंख्या है। साल २०११ की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या दो करोड़ ५५ लाख से ज्यादा है। अनुमान है कि इन दिनों राज्य की जनसंख्या तीन करोड़ आठ लाख के करीब है। आम धारणा है कि छत्तीसगढ़ बिहार से भी छोटा है। बिहार की जनसंख्या करीब तेरह करोड़ से कुछ ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ रकबा के लिहाज से बिहार से डेढ़ गुना बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के



मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने एकता नगर में ‘भारत पर्व-2025’ का प्रारंभ कराया

भारत पर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘राज्य अनेक-राष्ट्र एक’, ‘समाज अनेक-भारत एक’, ‘भाषा अनेक-भाव एक’ तथा ‘रंग अनेक-तिरंगा एक’ मंत्र को उजागर करता है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

एकता नगर में भारत पर्व द्वारा 15 दिनों तक समग्र भारत तथा भारतीय परंपराएँ पुनर्जीवित होने वाली हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

--: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हृदय में ‘स्व’ का नहीं, ‘समस्त’ व ‘राष्ट्रहित प्रथम’ का ही विचार रखा है
- प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा एकता नगर को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र बनाने का विजन दिया है
- एकता नगर प्रकृति, प्रगति एवं सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण के रूप में समग्र विश्व को ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की झुंकी कराता है
- प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर चलकर आत्मनिर्भर भारत तथा एक भारत-श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हों

--: ‘भारत पर्व-2025’ की विशेषताएँ :-

- भारत पर्व में देश के विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी
- प्रतिदिन शाम को दो-दो राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जाएंगी
- 45 फूड स्टॉल तथा एक लाइव स्टूडियो किचन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यंजन परोसे जाएंगे
- भारत दर्शन पैवेलियन में विभिन्न राज्यों के पैवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें उन राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाया जाएगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, आदिजाति विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा व अन्य महापुरुषों की उपस्थिति में ‘भारत पर्व-2025’ का शुभारंभ कराया। अखंड भारत के निर्माता तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उत्सव के हिस्से के रूप में एकता नगर में इस भारत पर्व का आयोजन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यह भारत पर्व प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र ‘राज्य अनेक-राष्ट्र एक’, ‘समाज अनेक-भारत एक’, ‘भाषा अनेक-भाव एक’ तथा ‘रंग अनेक-तिरंगा एक’ को चरितार्थ करता है। इस भारत पर्व में लोगों को ‘अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता’ का भाव प्रदर्शित करने वाली संस्कृति की झलक मिलने वाली है। श्री पटेल ने जोड़ा कि विश्व नेता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) के निर्माण द्वारा सरदार साहब को उतम श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सरदार साहब ने 562 रजवाड़ों के विलय से एक भारत का निर्माण किया

आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष प्रस्तुति आयोजित होगी



और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विकास के मार्ग पर श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब सोभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्रता के दशकों बाद हमें प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है, जिसने हृदय में ‘स्व’ का नहीं, ‘समस्त’ का – ‘राष्ट्रहित प्रथम’ का ही विचार रखा है। श्री पटेल ने आगे कहा कि स्वतंत्रता के बाद वर्षों तक सरदार जयंती केवल एक परंपरागत कार्यक्रम बन गई थी, परंतु हमारे मोदी साहब ऐसे विजनरी लीडर हैं कि जो किसी को न सूझे, वह उन्हें सूझता है। मोदी साहब ने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा भारत की एकता के लिए दिए गए बहुमूल्य योगदान

का यथोचित गौरव किया है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि मोदी साहब ने 2014 से सरदार साहब की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा देशवासियों को दी है। उन्होंने कहा कि सरदार साहब के विराट कार्य जितनी ही विराट विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से यह वनवासी प्रदेश विश्व के मानचित्र पर चमका है। वही व्यवस्थाएँ, वही प्रशासन, फिर भी यदि विशिष्ट विजन हो, तो स्थिति को कैसे बदला जा सकता है, यह मोदी साहब ने एसओयू एवं एकता नगर के निर्माण से सिद्ध किया है। भारत पर्व के विषय में श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस भारत पर्व में प्रतिदिन शाम को

दो-दो राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जाएंगी। 45 फूड स्टॉल तथा एक लाइव स्टूडियो किचन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 55 हस्तकला तथा महाराष्ट्र का गणपति उत्सव, बिहारियों का छठ पूजा उत्सव या पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा उत्सव; ये सभी उत्सव देश में जहाँ-जहाँ उन राज्यों के मूल निवासी परिवार रोजी-रोटी के लिए आकर बसे हैं, वहाँ सभी साथ मिलकर मनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि श्री नरेन्द्रभाई की प्रेरणा से माधवपुर का मेला राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना है।

को बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष प्रस्तुति आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत की तरह ही अनेकता में एकता की भावना हमारे उत्सवों-त्योहारों में भी साकार होती है। गुजरात का नवरात्रि – गरबा उत्सव, महाराष्ट्र का गणपति उत्सव, बिहारियों का छठ पूजा उत्सव या पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा उत्सव; ये सभी उत्सव देश में जहाँ-जहाँ उन राज्यों के मूल निवासी परिवार रोजी-रोटी के लिए आकर बसे हैं, वहाँ सभी साथ मिलकर मनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि श्री नरेन्द्रभाई की प्रेरणा से माधवपुर का मेला राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना है।

यह मेला पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम भारत को जोड़ता है। श्री मोदी के मार्गदर्शन में, सौराष्ट्र-तमिल संगम तथा काशी-तमिल संगम के आयोजन से भारत की एकता व अखंडता अधिक मजबूत हुई है। इसे यह भारत पर्व उजागर करता है। इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री ने देश के राज्यों के राजभवनों में भी अलग-अलग राज्यों के सईओ श्री अमित अरोड़ा, आदिजाति जाने के माध्यम से एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस भारत पर्व द्वारा 15 दिनों तक एकता नगर में समग्र भारत एवं भारतीय परंपराएँ पुनर्जीवित होने वाली हैं। प्रधानमंत्री की ‘विकास भी,

विरासत भी’ संकल्पना सच्चे अर्थ में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा एकता नगर को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए विजन दिया है और यहाँ सरदार साहब की प्रतिमा के साथ-साथ अनेक पर्यटन आकाशंघा आयाम जोड़े हैं। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का भी संकल्प किया है। इसके लिए उन्होंने सरदार साहब के दिखाए एकता के मार्ग पर चलकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भारत पर्व के विभिन्न स्टॉल की मुलाकात ली। इस अवसर पर सांसद श्री जशुभाई राठवा, विधायक डॉ. दर्शनाबेन देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भीमसिंह तडवी, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएल) के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश पुरी, पर्यटन सचिव श्री राजेन्द्र कुमार, गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) के प्रबंध निदेशक श्री प्रभव जोशी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सईओ श्री अमित अरोड़ा, आदिजाति विकास आयुक्त श्री आशिष कुमार, जिला कलेक्टर श्री एस. के. मोदी, जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) श्री आर. बी. वाळा, पुलिस महानिदेशक श्री संदीप सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री विशाखा डबराल, एसओयू के अपर कलेक्टर श्री गोपाल

जनसुनवाई में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई — संभल में 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, SP ने दी सख्त चेतावनी

(जीएनएस)। संभल। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। जनसुनवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिस्नोई ने एक साथ 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये सभी पुलिसकर्मी जिले के अलग-अलग थानों में तैनात थे और जनशिकायतों के निस्तारण में उदासीनता दिखाने के दोषी पाए गए। एसपी बिस्नोई ने कहा कि यह कार्रवाई जनता के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि “जनसुनवाई में लापरवाही, शिकायतों की अनदेखी या जनता से दुर् व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुने और उसका समाधान करे।” लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में कई थानों के मुख्य आरक्षी और आरक्षी शामिल हैं। इनमें कोतवाली संभल से आरक्षी राजपाल सिंह और मुख्य आरक्षी सह चालक बलराज, थाना हयातनगर से चालक रूपचंद्र, आरक्षी नीरज कुमार और आरक्षी यादव, थाना कैलादेवी से मुख्य आरक्षी अशोक कुमार और सत्येंद्र कुमार शर्मा, थाना हजरतनगर गढ़ी से आरक्षी मोहित कुमार और मुख्य आरक्षी सोवरन सिंह, थाना नखासा से आरक्षी अनिरुद्ध चौधरी और सहचालक आकाश जुरेल, थाना असमोली से आरक्षी रोबिन राठी और भोलू तोमर, तथा थाना रायसती से मुख्य आरक्षी अरुण सिवाल और आरक्षी गौरव शर्मा के नाम प्रमुख रूप से

शामिल हैं। एसपी बिस्नोई ने कहा कि जनता की शिकायतें पुलिस विभाग के लिए प्राथमिकता हैं, और किसी भी स्तर पर उच्छा पाए जाने पर जिम्मेदारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी — “अविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मी यदि जनता के प्रति असंवेदनशील या लापरवाह पाया गया, तो उसके खिलाफ निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक की कार्रवाई की जाएगी।” इस कार्रवाई को जिले में पुलिस अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कार्यवाही माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इसे एक “सकारात्मक और आवश्यक कदम” बतते हुए कहा कि इससे जनसुनवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गंभीरता बढ़ेगी, और आम जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत होगा।

गौप्रेमी प्रधानमंत्री का जन्मस्थल बनेगा गौसेवा का तीर्थधाम

- ‘गाय से गाँव’ की कायापलट करने की अभूतपूर्व दूरदर्शिता
- विरासत-संस्कृति-पर्यटन-अर्थव्यवस्था का संगम
- साधारण गौशाला से बढ़कर अत्याधुनिक ग्रामीण प्रयोगशाला

शासन-प्रशासन की कवायद शुरू

14.98 करोड़ रुपए यानी करीब 15 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रस्तावित वृंदावन गौचर पार्क के निर्माण का पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल प्रस्ताव के रूप में है और नगर पालिका व जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर शहरी विकास विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा वृंदावन गौचर प्रोजेक्ट को अनुमोदन दे दिया गया है। राज्य स्तर पर गुजरात शहरी विकास कंपनी (जीयूडीसी) इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी होगी, जबकि पालिका स्तर पर भूमि अधिग्रहण सखित समग्र निर्माण प्रक्रिया की जाएगी।



गाय आधारित ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बनेगा पार्क

वृंदावन गौचर पार्क के नाम से इतर कि इस प्रोजेक्ट के विजन में सिर्फ गाय ही नहीं, बल्कि गाँव है। इस पार्क की परिकल्पना और इसके लक्ष्यों पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक ‘गाय आधारित ग्रामीण विकास’ का आदर्श मॉडल बनेगा। इस प्रोजेक्ट में ‘गाय से गाँव’ की कायापलट की अभूतपूर्व विजन है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का संचार करेगा। यह केवल एक गौशाला नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ग्रामीण प्रयोगशाला और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र होगी, जहाँ परंपरा और तकनीक का संगम होगा। पार्क को एक ‘रूरल इन्वेनशियल हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार की इस एक प्रोजेक्ट के जरिये गाय से लेकर गाँव-किसान-पशुपालक, तक सभी के भविष्य को उन्नत बनाने की योजना है।

डेयरी विकास, रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण शामिल

प्रोजेक्ट के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य में सुधार क्षेत्र में समय पर उपचार और बेहतर पोषण से गायों की उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, दूध व डेयरी उत्पादों की बिक्री से पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाने, पशु चिकित्सा, डेयरी उद्योग, परिवहन और विपणन में नए कार्यों से रोजगार के नए अवसर सृजित करने, बायोगैस तथा जैविक खाद से प्रदूषण में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि से पर्यावरण संरक्षण करने, आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग से तकनीकी उन्नति लाने, विरासत और कृषि पर्यटन के नए गंतव्य के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा देने, डेयरी उत्पादन एवं सहकारी समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से महिला सशक्तिकरण करने, गांव में एकजुटता और आत्मनिर्भरता का भाव लाकर सामुदायिक विकास करने, जैविक खाद और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर कृषि विकास करने जैसे विशाल लक्ष्य रखे गए हैं।



विरासत-संस्कृति-पर्यटन-अर्थव्यवस्था का संगम

यह गौचर पार्क वडनगर के प्राचीन मंदिरों, बावड़ियों, ऐतिहासिक किले और विरासत स्थलों के साथ जुड़कर एक नए पर्यटन परिपथ का निर्माण करेगा। पर्यटक यहाँ आकर ग्रामीण जीवन, पशुपालन की आधुनिक तकनीक और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को नजदीक से देख सकेंगे। यह स्थान ‘एग्री-टूरिज्म’ और ‘कल्चरल टूरिज्म’ का नया केन्द्र होगा। पार्क में स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के लिए यहाँ बाजार और प्रदर्शनियों का आयोजन संभव होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।

पर्यटनीय स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल बनेगा गौचर पार्क

इस पार्क के निर्माण का प्रार्थमिक उद्देश्य वडनगर के सड़क मार्गों को आवाग पशुओं से मुक्त बनाना है। इस पार्क में गायों के लिए चारागाह के अनुरूप घास-चारे व पानी की व्यवस्था होगी; तो इन पशुओं की स्वस्थ देखभाल के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। यह पार्क सैसीटीवी कैमरा निगरानी से लेस होगा। पार्क में भिक्क प्रोटेसिंग प्लॉट तथा अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पार्क में गायों की अच्छी नस्लों के फालन-पोषण के प्रयास भी किए जाएंगे। ये सारे उपक्रम इस वृंदावन गौचर पार्क को एक पर्यटनीय स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल भी बनाएंगे।

गुजरात देगा पूरे देश को संदेश

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ के विजन के अनुरूप इस प्रोजेक्ट के जरिये गुजरात पूरे देश को संदेश देगा कि गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि आर्थिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति भी है। जब वृंदावन गौचर पार्क अपनी पूरी भव्यता में तैयार हो जाएगा, तब यह वडनगर के लिए केवल एक सुविधा नहीं, अपितु एक नई पहचान होगा। वडनगर एक ऐसा स्थान बनेगा; जहाँ इतिहास, संस्कृति, विकास और नवाचार एक साथ सँ लेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संदर्भ में बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

राज्य सरकार फसलों को हुए नुकसान की तत्काल समीक्षा-सर्वेक्षण कर किसानों को उदारतम सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हाल ही में राज्य में हुई बेमौसम बरसात और मौसम में आए बदलाव के कारण फसलों को हुए नुकसान के संबंध में पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों की आपदा के समय उनके साथ खड़े रहने के दिशा-निर्देश दिए हैं। राज्य में इस वर्ष असाधारण हालात में यह बेमौसम बारिश हुई है। इसके कारण किसानों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। ऐसे में, राज्य सरकार का उद्देश्य संपूर्ण किसान हितैषी दृष्टिकोण के साथ किसानों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, राज्य में पिछले दो दशकों से अधिक समय में ऐसी बेमौसम बरसात नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इस वर्ष ऐसी बेमौसम बारिश के कारण किसानों को जो नुकसान झेलना पड़ा है, उसकी तत्काल समीक्षा-सर्वेक्षण करके किसानों को उदारतम सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन



असाधारण परिस्थितियों में हुई बेमौसम बरसात तथा उसकी व्यापकता को देखकर मुख्य सचिव और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ऐसे हालात शायद ही कभी उत्पन्न होते हैं, इसलिए विशेष संवेदनापूर्वक राज्य के किसानों के हित में प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को, हुए नुकसान का पंचनामा और आवश्यक कार्रवाई कर कामकाज को इस तरह से 3 दिनों के भीतर इस प्रकार पूरा करें कि किसानों को कोई परेशानी हो,

करें और तीन दिनों में समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को भेजें। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ये व्योरा जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचें ताकि राज्य सरकार नुकसान से प्रभावित किसानों की सहायता कर सके। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में इस संदर्भ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में कृषि फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए और संबन्धित जिलों के नुकसान का जेलीबाड़ी अधिकारियों को तुरंत इस विषय में सूचित करने के आदेश दिए, ताकि किसानों को हुए नुकसान को लेकर सहयोग करने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन असाधारण हालातों और राज्य के किसानों की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पंचनामा

जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक उछाल : अक्टूबर में 1.96 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वसूली, छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ आसान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर 2025 का महीना बेहद उत्साहजनक रहा। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन ने अब तक का सर्वाधिक स्तर छु लिया है। कुल 1.96 लाख करोड़ रुपये की वसूली के साथ यह एक नया रिकॉर्ड बन गया है। यह पिछले साल की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत, व्यापारिक गतिविधियाँ और कर अनुपालन तीनों में स्थिर सुधार हो रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 1.89 लाख करोड़ और अगस्त में 1.86 लाख करोड़ रुपये था। लगातार तीन महीनों से राजस्व में यह वृद्धि यह दर्शाती है कि आर्थिक गति पुनः तेज हो रही है और करदाताओं में पारदर्शिता तथा ई-वैनरनर पर भरोसा लगातार बढ़ा है। 22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी 2.0 को इस तेजी का प्रमुख कारण माना जा रहा है। सरकार ने इस संशोधित ढांचे में टैक्स प्रणाली को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए बड़े बदलाव



किए हैं। अब देश में केवल दो प्रमुख टैक्स स्लैब — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत — लागू हैं। पहले मौजूद 12 उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई हैं। अक्टूबर तरह समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि, लज्जरी आइटम्स और ‘सिन गुड्स’ जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर विशेष 40 प्रतिशत जीएसटी दर रखी गई है। इन बदलावों से बाजार में स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। लगभग 375 वस्तुओं, जिनमें किचन उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, होम अप्लायंसेज और आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, की कीमतें घट गई हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है और बाजार में मांग बढ़ी है,

जिसके परिणामस्वरूप टैक्स वसूली भी स्वाभाविक रूप से ऊँची रही। सरकार के अनुसार, जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर 2025 में रिफंड की राशि 39.6 प्रतिशत बढ़कर 26,934 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। वहीं, सकल घरेलू राजस्व (ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू) 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इंपोर्ट पर वसूले गए टैक्स में भी 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 50,884 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। इस सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य के बीच सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। आज

से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो गया है, जो पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित है। जिन कारोबारियों का मासिक टैक्स 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें अब मैन्युअल दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका आवेदन तीन कार्यदिवस के भीतर स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। यह सुविधा छोटे और मझोले उद्यमों (MSME सेक्टर) के लिए समय और संसाधनों की बड़ी बचत साबित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन का यह बढ़ता हुआ रुझान केवल राजस्व वृद्धि नहीं, बल्कि आर्थिक पुनरुद्धार और सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का संकेत भी है। भारत का कर ढाँचा धीरे-धीरे विश्वस्तरीय पारदर्शिता और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले महीनों में राजस्व और निवेश दोनों में और मजबूती की संभावना जताई जा रही है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में यह रुझान और तेज होगी तथा चालू वित्त वर्ष के अंत तक जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये है। इस सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य के बीच सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। आज

चार मंत्रियों के चलते दिल्ली सरकार के लोगो की लॉन्चिंग टली, अब सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा एलान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह यानी ‘लोगो’ जारी होने का इंतजार अब कुछ और लंबा हो गया है। शनिवार को दिल्ली दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन चार मंत्रियों के दिल्ली से बाहर होने की वजह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब तक इसे जारी नहीं किया जाएगा। अब लोगो की लॉन्चिंग बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही की जाएगी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, चार प्रमुख मंत्री इन दिनों बिहार में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में व्यस्त हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को आगे

बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान, संस्कृति और विकास की कहानी है, इसलिए इसे आधे अधूरे मन से जारी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री चाहती हैं कि इस प्रतीक में हर मंत्री की सहमति और दिल्ली की आत्मा का समावेश हो। दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि लोगो डिजाइन को लेकर सरकार के भीतर लगातार चर्चा जारी है। इस प्रतीक को राजधानी की विरासत और आधुनिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाले रूप में तैयार किया गया है। इसमें संस्कृति, लोकतंत्र, नवाचार और नागरिक भागीदारी के भावों को एकसाथ जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह लोगो न

केवल दिल्ली की पहचान बनेगा बल्कि इसे एक वैश्विक ब्रांड छवि भी प्रदान करेगा। दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य को अपना आधिकारिक प्रतीक मिलने जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल की शुरुआत में MyGov प्लेटफॉर्म पर लोगो डिजाइन करने के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 1,800 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रविष्टियाँ भेजीं। इन डिजाइनों में से कुछ सर्वश्रेष्ठ नमूनों को चयन समिति ने चुना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया। बताया जाता है कि जिस डिजाइन को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वह दिल्ली के ‘इतिहास और इनोवेशन के सह-अस्तित्व’ को खूबसूरती से दर्शाता है।

मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार, रेखा गुप्ता चाहती हैं कि दिल्ली को यह प्रतीक भविष्य की राजधानी की दिशा



दिखाए — एक ऐसी राजधानी जो पारदर्शी, आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम और नागरिक-केंद्रित शासन की प्रतीक हो। लोगो में दिल्ली की धरोहरों जैसे लाल किला, इंडिया गेट या अशोक

लग्न समारोह में गोली चली, युवक की मौके पर मौत — हुड़दंग रोकने पर बढ़ा विवाद, तीन आरोपी फरार, गांव में तनाव

(जीएनएस)। रेवाड़ी जिले के पीथड़ावास गांव में शुक्रवार देर शाम खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया जब एक लान समारोह के दौरान हुड़दंग रोकने पर कहासुनी के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना इतनी अचानक हुई कि पूरे समारोह में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। मृतक की पहचान बधराणा गांव निवासी 30 वर्षीय इन्द्रजीत सिंह के रूप में हुई है, जो बिजली मिस्त्री के रूप में काम करता था। जानकारों के अनुसार शुक्रवार रात पीथड़ावास गांव में एक लग्न समारोह चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवक नशे की हालत में हुड़दंग कर रहे थे और शादी के कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे। यह देख कर समारोह में शामिल इन्द्रजीत सिंह ने उन्हें समझाया कि वे शांति बनाए रखें और कार्यक्रम में अशांति न फैलाएं। लेकिन यह बात हुड़दंग में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो रहे युवकों को नागवार गुजरी और बातों-बातों में कहासुनी इगई में बदल गई। इसी बीच उनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकालकर इन्द्रजीत पर सीधा फायर कर दिया। गोली उसके गर्दन में लगी, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया।



गोली चलने के बाद हमलावरों ने 3-4 राउंड हवाई फायर भी किए और मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनते ही समारोह में भगदड़ मच गई। परिजन और ग्रामीण घायल इन्द्रजीत को अस्पताल ले जाने की कोशिश में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर रामपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पास के गांव मनेठी के रहने वाले हैं।

पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया है। शनिवार को जब मृतक के पोस्टमार्टम में देरी हुई, तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रामपुरा थाना के बाहर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। इससे गोपालदेव चौक पर लंबा जाम लग गया और यातायात ठप हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार खुद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझ-बुझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद दोपहर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और

शाम को मृतक इन्द्रजीत सिंह का अंतिम संस्कार उसके पैनूक गांव बधराणा में गमगीन माहौल में किया गया। इन्द्रजीत सिंह की चार साल पहले शादी हुई थी और उसकी तीन साल की एक बेटी है। उसकी असमय मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मनेठी गांव के तीन युवकों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में छाई धुंध, यूपी-बिहार में बारिश के आसार, हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर से सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ठंडक का असर बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह दिल्ली की हवा धुंध और स्मॉग की परत में लिपटी नजर आई, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। वहीं, मौसम विभाग (IMD) ने 1 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान बताया है। दिल्ली के कई जिलों में भी हल्की से बारिश के कई जिलों में बृढ़ावादी की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 5 नवंबर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों — जैसे चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ — में भारी बर्फबारी की संभावना है।

ऑनलाइन गेमिंग ऐप के बहाने ठगी करने वाला गिरोह धराया, मोहाली पुलिस की बड़ी सफलता

(जीएनएस)। मोहाली। साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए मोहाली पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले मामले में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे मामले में एक 80 वर्षीय महिला को 2 करोड़ रुपये की डिजिटल ठगी से बचाया गया। दोनों मामलों की निगरानी एसएसपी हरमन हंस और एसपी रूपिंदर सोही ने की। पहले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय कुमार निवासी डीसी कॉलोनी सिरसा (हरियाणा), सितेश निवासी निहार रेजीडेंसी (गुजरात) और चेतन निवासी गांव सगुरिया (गुजरात) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि ये तीनों एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जिो गेमिंग ऐप्स के जरिए भोले-भाले लोगों को ऑनलाइन लुभाकर ठगी करते थे। इनके खिलाफ साइबर थाना फैज-7 में बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरोह के काम करने का तरीका बेहद



चालाकी भरा था। ये लोगों को गेमिंग ऐप में निवेश के बहाने झांसे में लेते, फिर उनके बैंक खातों से धीरे-धीरे रकम निकाल लेते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरड़ के सनी एन्क्लेव इलाके में एक घर से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और मौके से तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

सिंह बैक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आंध्रा मिली थी कि खरड़ के सनी एन्क्लेव इलाके में एक घर से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और मौके से तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

तक पहुंचा जा सके। दूसरे मामले में पुलिस ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को साइबर ठग से बचाया। आरोपी ठगी ने वीडियो कॉल के जरिए महिला को “डिजिटल गिरफ्तारी” का डर दिखाया और उनसे 12 करोड़ रुपये ट्रॉसफर करने की मांग की थी। वे तीन दिनों तक लगातार धमकाते रहे, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई। साइबर टीम ने तत्काल कार्रवाई कर महिला को ठगी से बचा लिया। पुलिस ने दोनों घटनाओं के बाद नागरिकों को आगाह किया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, वेबसाइट या ऑनलाइन इनपुत याचना पर परांपरा न करें। साइबर पुलिस ने अपील की है कि ठगी से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 से संपर्क करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दें। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित किया है कि साइबर अपराधों अब पारंपरिक अपराधों से कहीं अधिक सक्रिय हैं, और आम जनता को सतर्क रहकर ही अपने डिजिटल जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

चलती बस में आग लगने पर कौन होगा जिम्मेदार ? यात्रियों की सुरक्षा अब RTO की निगरानी में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में चलती बसों में आग लगने की घटनाओं ने सरकार का ध्यान एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा की ओर खींचा है। आए दिन सड़क पर बसों में अचानक आग भड़कने की खबरें आती रहती हैं, जिनमें कई बार यात्रियों की जान पर बन आती है। अब सरकार ने इस गंभीर समस्या पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अब से किसी भी बस को तभी फिटनेस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जब वह “बस बॉडी कोड” के सभी मानकों पर खरी उतरेगी। इन मानकों की जांच की जिम्मेदारी अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTOs) को सौंपी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें बसों में आग लगने की घटनाओं और यात्रियों की सुरक्षा को



लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में यह पाया गया कि देश के कई हिस्सों में अब भी बड़ी संख्या में बसें “बस बॉडी कोड” के मानकों का पालन नहीं करती। इस पर मंत्री ने सभी राज्यों के परिवहन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि बिना इन मानकों के पालन के किसी भी बस को सड़क पर उतरने की अनुमति न दी जाए।

क्या है बस बॉडी कोड और क्यों

है जरूरी ?

बस बॉडी कोड एक सुरक्षा मानक प्रणाली है जिसे सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2016 में तैयार किया था और 2017 में इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत बसों के निर्माण से लेकर अंदरूनी सुरक्षा उपकरणों तक के लिए कई अनिवार्य नियम तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य बसों को आग, दुर्घटना या आपात स्थिति में यात्रियों के

लिए अधिक सुरक्षित बनाना है। कोड के अनुसार, हर बस में कम से कम चार आपातकालीन दरवाजे (450 मिमी चौड़ाई के) होना आवश्यक है ताकि किसी भी स्थिति में यात्रियों की निकासी सुगमता से हो सके। बसों के अंदर फायर-रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेसन सिस्टम (FDSS), तथा शीशे तोड़ने के लिए आपातकालीन हथौड़े रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही बस की पूरी वायरिंग और इंजन कंपार्टमेंट में ऐसे उपकरण लगाने होंगे जो आग फैलने से रोकें।

आरटीओ की भूमिका अब और सख्त

अब देशभर के आरटीओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बस का फिटनेस सर्टिफिकेट या नया रजिस्ट्रेशन तभी जारी होगा जब वह बस बॉडी कोड के सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करेगी। किसी भी बस के निरीक्षण के दौरान यदि ये सुरक्षा

केन्या में भीषण भूस्खलन से मचा कहर, 21 लोगों की मौत, 30 से अधिक लापता, हजारों बेघर हुए

(जीएनएस)। पश्चिमी केन्या के रिफ्ट वैली क्षेत्र में शनिवार को हुई भयानक प्राकृतिक आपदा ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। एलेयो मारकेट काउंटी के चेसोनगोच नामक पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही वर्षा ने इस क्षेत्र की मिट्टी को कमजोर कर दिया था, जिसके कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक खिसक गया और नीचे बसे गांवों को निलग गया।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस भूस्खलन ने करीब एक हजार से अधिक मकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और अब खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए सेना, राष्ट्रप्री आवाद प्रबंधन बल और पुलिस को लगाया है। भारी बारिश और कीचड़ के कारण राहत कार्यों में भारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन भयावकमी लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे

शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता देगी। उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर रूप से घायल 30 लोगों को हवाई मार्ग से एलडोरेट शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों की पहचान कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। चेसोनगोच और उसके आसपास के क्षेत्र को आपदा-प्रवण इलाका माना जाता है। इससे पहले वर्ष 2010 और 2012 में गृह मंत्री किचुम्बा मुकोमेंने ने घटना पर



हैं। स्थानीय निवासी स्टीफन किटनी ने एक स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि हादसे से ठीक पहले उन्होंने पहाड़ की ओर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वह आवाज सुनते ही उन्होंने अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भागने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उनका पूरा घर मिट्टी के सैलाब में समा गया। उन्होंने कहा कि उनके कई पड़ोसी अब तक लापता हैं और पूरी बस्ती तबाह हो गई है।

लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2020 में आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके को तहस-नहस कर दिया था, जिसमें एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर तक बह गया था। स्थानीय भूभाग विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र की पहाड़ियों की बनावट बेहद अस्थिर है और लगातार बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि यहां भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित वनों की कटाई ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। इस भयानक आपदा के बाद देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति और शीर्ष नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राहत एजेंसियाँ अब भी मलबे में दबी जानों को बचाने के लिए रात-दिन जुड़ी हैं, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। चेसोनगोच का यह भूस्खलन केन्या के इतिहास में दर्ज एक और दर्दनाक घटना है, जहां प्राकृति का कहर, जलवायु परिवर्तन की चेतावनी और मानव जीवन की असुरक्षा एक बार फिर भयावह रूप में सामने आई है।